issue of introduction of a Gold Bank as a National Scheme to the High Level Committee on Balance of Payments set up under the Chairmanship of Dr. C. Rangarajan. The High Level Committee examined the commercial viability of the scheme and other details and in it's Report of April 1993 recommended, inter alia, caution in creating permanent institutions or corporate bodies for mobilising gold. Government has accepted the recommendation of the High Level Committee and has dropped the issue of setting up a Gold Bank for the time being.

Facilities provided by World Bank and IMF

2646. SHRI SYED SIBTEY RAZI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the World Bank and the International Monetary Fund have taken soft life on some of the crucial policy issues like reduction of subsidy and formulation of early exit policy;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether these steps have helped the country while working out Budget proposals for 1994-95;

(d) if so, the details thereof;

(e) whether these facilities will enable Government to achieve their targets fixed for 1994-95; and

(f) if so, the details thereof and if not, the details of further steps to be taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. ABRAR AHMED): (a) to (f) Necessary provisions have been made in the Budget proposals for '94-95' for the National Renewal Fund. As part of its process of fiscal consideration, the Government is aiming at better targetting of subsidies for enhanced efficiency. The budget proposals are based entirely on the Government of India's own assessment of the requirements of the economic and the national interests.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को हुआ घाटा

2647. **श्री विष्णु कान्त शास्त्री**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 14,500 से अधिक शाखाओं को चलाने में प्रति दिन एक करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस घाटे को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये हैं;

(ग) क्या इस घाटे को दूर करने के लिये आल इंडिया ग्रामीण बैंक वर्कर्स आर्गेनाइजेशन ने एक राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित करने का सुझाव दिया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अबरार अहमद): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया हैं कि वर्ष 1992-93 के दौरान, 172 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 327.26 करोड़ रुपए की हानियां हुई थीं। उनकी अर्थक्षमता में, कम समय में सुधार लाने की दृष्टि से, दिसम्बर, 1993 में उपायों का एक पैकेज घोषित किया गया था। इन उपायों में गैर-लक्ष्यगत समूह वित्तपोषण को 40% से बढ़ा कर 60% करना गैर-निधि पर आधारित कारोबार में वृद्धि, उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सेवा क्षेत्र संबंधी बाध्यताओं से मुक्त करना जिनका वर्ष 1992-93 में संवितरण